



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]
No. 445]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, मई 4, 2006/वैशाख 14, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2006/VAISAKHA 14, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2006

का.आ. 646(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अन्तिम बार समीक्षा 3 नवम्बर, 2005 को की गई थी जिसके आधार पर असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 4 मई, 2006 तक बढ़ा दिया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :—

- (i) असम राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बड़ी संख्या में हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही गुट अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दा ओगाह (डीएचडी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं;
- (ii) यतः, उल्फा तथा एन डी एफ बी प्रभुसत्ता की मांग कर रहे हैं, यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएम) तथा डी एच डी पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। केएलएनएलएफ की मांग में भी अलगाव के स्वर हैं;
- (iii) उपर्युक्त गुटों में से कुछ का सशस्त्र संघर्ष में विश्वास बना हुआ है और उनमें से अधिकांश आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने तथा लोगों से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसक कार्यों में लिप्त हैं;

- (iv) असम की सीमा से लगे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड की 20 किमी. चौड़ी पट्टी में विद्रोही गुटों जैसे उल्फा, एन डी एफ बी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट, पीपुल्स लिबरेशन ऑफ (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), अचिक नेशनल वॉलंटीयर काउंसिल (एएनवीसी), हाइनीडूफ नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आदि की हिंसक गतिविधियां जारी हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत और छः महीने के लिए अर्थात् 4-11-2006 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2006

S.O. 646(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990;

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, along their border with the State of Assam as 'disturbed area';

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas;

And, whereas, the last review of law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas was conducted on the 3rd November, 2005 on the basis of which the period during which the State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall be 'disturbed area' was extended up to 4th May, 2006;

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam indicates the following :—

- (i) the law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLFF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam;
- (ii) while the ULFA and the NDFB have been demanding sovereignty, the United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) and the DHD are demanding separate States. The demand of the KLNLFF also has secessionist overtones;
- (iii) some of the above mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from the people;
- (iv) in the 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam the violent activities of insurgent outfits such as the ULFA, the NDFB, the two factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the People's Liberation Army (PLA), National Liberation Front of Tripura (NLFT), Achik National Volunteer Council (ANVC), Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) etc. continue.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall continue to be "disturbed area" under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a further period of six months, *i.e.*, up to 4-11-2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.